Dr Kumari Maya
H.O.D.
Deptt of Eco.

Sources of Service Sector Growth:

Service Sector in the Indian Economy:

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। परन्तु जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होती गई आर्थिक गतिविधियों में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता चला गया। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी मिली जैसे बैंकिंग व बीमा, परिवहन, व्यापार, संचार इत्यादि। विभिन्न देशों में इस प्रकार के विकास पैटर्न के मद्देनज़र कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे फीशर, क्लार्क, रोस्टोव तथा कुज़नेट्स ने तर्क दिया कि विकास तीन-चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया में सेवा क्षेत्र विकास के तीसरे चरण से जुड़ा हुआ है परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हाल के वर्षों में तेजी आई है उसका कारण सेवा क्षेत्र में गतिशीलता रही है। सेवा क्षेत्र का अब भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 57 प्रतिशत है तथा पिछले करीब दो दशक में भारत की संवृद्धि में उसका 60 प्रतिशत से अधिक योगदान रहा है। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि भारत का विकास-पथ जो सेवा निर्देशित विकास पथ है, Sustainable (धारणीय) नहीं है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यदि अर्थव्यवस्था के वास्तविक वस्तु उत्पादक क्षेत्र कृषि तथा उद्योग तेजी से प्रगति नहीं करते तो सेवा-क्षेत्र पर आधारित विकास-पथ बहुत लम्बे समय तक बना नहीं रह सकता।

सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा (Shares of service in GDP): हाल की अवधि में सेवा क्षेत्र में तेज संवृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सकल घरेलू में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 1980-81 में 38.0 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 42.7 प्रतिशत तक और 1913-14 में 59.9 प्रतिशत पहुँच गया। जहाँ सकल वर्धित मूल्य (GVA) का प्रश्न है, GVA मूल कीमतों पर सेवाओं का हिस्सा 2014-15 में 52.2 प्रतिशत तथा 2015-16 में 53.2 प्रतिशत था। वस्तुतः 1991 के बाद की सुधार-अवधि में सेवा क्षेत्र के हिस्से में तेज वृद्धि हुई है।

TECHNOLOGY - INFORMATION AND COMMUNICATIONS (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी): हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र के तेज विकास में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) Sector की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ICT के अन्तर्गत माईक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग (हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर), दूर संचार तथा आप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, सेमी कंडक्टर, फाइबर आप्टिक्स आते हैं। एक मजबूत ITC आधार संरचना, विश्वभर के सूचना के शीघ्र व कुशल प्रसार में अत्यधिक सहायक हैं। हाल के वर्षों में उपार्जित ज्ञान से विभिन्न प्रौद्योगिकी कार्यों में हो रहे अनुसंधानों से ज्ञान के उत्पादन, भंडारण तथा उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जो कई आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। ICT के उपयोग से सेवाओं में सुधार हो रहा है तथा नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विशेष रूप से नई प्रौद्योगिकी की बेहतर कार्यकुशलता तथा अनुसंधानों से विनिर्माण, व्यापार, कृषि, राजकीय व्यवस्था तथा सरकारी सेवाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। समय व स्थान की दूरियां कुल स्वरूप में कम हो रही हैं, वस्तुओं व सेवाओं के व्यापक पैमाने पर उत्पादन में सहायता कर रहा है, तथा सीमित उत्पादन के साधनों की भरपाई कर रहा है।

नेटवर्क का काल (The Network Age) : उत्पादन व अन्य गतिविधियों की सांगठनिक पुनर्गठन ऐसे नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है जो विश्वव्यापी है। औद्योगिक काल में जब सूचना का आदान प्रदान, संचार तथा परिवहन, अपेक्षाकृत महंगा था कम्पनियों तथा संगठनों का vertical integration (उर्ध्वाधर एकीकरण) सही नीति थी परन्तु नेटवर्क काल में जब सूचना तथा संचार की लागत लगभग नगण्य हो गई है, समानान्तर एकीकरण (Horizontal integration) सही है। यही कारण है कि अब उत्पादन का संगठन अलग-अलग कम्पनियों व इकाइयों के माध्यम से किया जा रहा है – उपठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रयोगशालाओं, प्रबन्ध सलाहकारों, शिक्षा व शोध संस्थाओं, बाजार अनुसंधान फर्मों, वितरकों इत्यादि के माध्यम से। ये नवीन परस्पर निर्भरता, जिसमें प्रत्येक कड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मूल्य वर्द्धन की श्रृंखला का सृजन करती है, "नया युग गतिविधियों के कई क्षेत्रों में विश्वव्यापी नेटवर्कों का सृजन कर रहा है जब ये नेटवर्क एक न्यूनतम आकार को प्राप्त कर लेते हैं तब वे प्रौद्योगिकी के प्रसार तथा उसके प्रभाव को निर्धारित करने वाले कारक बन जाते हैं।" Human Development Report 2001.

वैज्ञानिक अनुसंधान व नवप्रवर्तन (Scientific research and innovation) – विश्वविद्यालयों के बीच आरंभिक संचार प्रक्रियाओं का नेटवर्क, जिसने इंटरनेट में जान फूंकी, अब संस्थाओं और देशों के बीच अधिकाधिक सहयोग रूप ले रहा है।

उत्पादन (Production) : विश्वभर में काम कर रहे बड़े निगम जिनका मुख्यालय अधिकतर उत्तरी अमेरिका, यूरोप या जापान होता है परन्तु जिनकी सुविधाएं कई देशों में फैली हुई हैं, कई नये देशों में अपनी गतिविधियों के विस्तार द्वारा विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलाएँ बना रहे हैं।

डियासपोरा (Diaspora) : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए तेजी से बढ़ रही मांग के कारण वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की विश्वव्यापी गतिशीलता में तेज वृद्धि हुई है। जब ये लोग विकासशील देश से आते हैं तो उनका विश्वव्यापी फैलाव व अनुभव उनके अपने देश के लिए कई क्षेत्रों में जैसे वित्त के क्षेत्र में, व्यावसायिक संपर्कों के क्षेत्र में बहुमूल्य नेटवर्क बनाने में सहायता प्रदान करता है।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आरंभिक काल में सरकार की भूमिका अत्यंत सीमित रही। रफीक दोसानी का तो यहाँ तक कहना है कि आरंभिक काल में भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के प्रति नीति की यदि कोई प्रतिपत्ति या विशेषता थी तो वस्तुतः सापेक्ष केवल उपेक्षा की नीति थी। उद्योग के आरंभिक काल को इस उद्योग के विकास का श्रेय मुख्यतया निजी उद्यमियों को जाता है। इस संदर्भ में दोसानी दो बातों की चर्चा करते हैं: प्रथम देश में कई ऐसे योग्य इंजीनियर थे जिन्होंने पिछले दशकों में देश के सर्वोत्तम कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त की थी परन्तु जिन्हें भारत में बहुत कम विकास का अवसर मिल पाए। अब वे देश को, इनमें से कई लोग विदेशों में काम करने चले गए। अब वे देश में ही उपलब्ध कई उद्यम स्थापित करने की स्थिति में थे तो देश में ही उपलब्ध कई उत्तम इंजीनियरिंग स्नातक उनको साथ मिल गए, काम करने के लिए उपलब्ध थे। दूसरे अमेरिकी इंजीनियरिंग कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करके जो प्रवासी देश लौटे उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए कुछ बड़े औद्योगिक समूह सहायता देने के लिए तैयार थे। 1980 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असीमित संभावनाओं के द्वार खोल दिए। अब programmers के लिए यह संभव हो गया कि वे विश्व के किसी भी कोने में बैठकर किसी के लिए भी programming कर सकते थे। उनको उसके काम के लिए मात्र एक workstation की तथा एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर प्रणाली की आवश्यकता थी। अर्थात अब programmers के लिए यह जानना आवश्यक नहीं था कि वे किस फर्म के हार्डवेयर हेतु काम कर रहे हैं या फिर उनके programme का किस तरह का अंतिम उपयोग किया जाना था।

इसी दौरान सरकार के नीति में भी परिवर्तन होना शुरू हुआ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने अपनी उदारीकरण तथा संरक्षण की नीति का परित्याग किया तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणाओं व प्रोत्साहनों की घोषणा की। इस संदर्भ में एक मुख्य बात थी 1984 में घोषित नई कंप्यूटर नीति (New Computer Policy 1984) इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे।

(1) देश में कंप्यूटरों के उत्पादन को इस प्रकार प्रोत्साहन देना जिससे विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कंप्यूटरों का देश में ही उत्पादन हो सके तथा इस उत्पादन में बढ़ते हुए पैमाने पर घरेलू घटकों व तकनीकों का प्रयोग किया जाए। घरेलू स्रोतों से अथवा विदेशों से

(2) प्रयोग कर्ताओं को उपयोग के लिए कंप्यूटर आयात करने की सुविधा तथा

(3) कंप्यूटरों के ऐसे उपयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन और विकास को बढ़ाने में सहयोग देना।

देश में कंप्यूटरों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के रियायतों व प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई जैसे:

(i) सहयोगी उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर शुल्क में कमी,

(ii) कंप्यूटर-आधारित प्रणालियों एवं सहयोगी पदार्थों, तकनीकि ज्ञान, डिजाइन, ड्राइंग इत्यादि के आयात के शर्तों में ढील, तथा

(iii) जो सहयोगी उत्पाद देश में उपलब्ध नहीं हैं उन पर आयात शुल्क में कमी। नई Computer नीति 1984 में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पर आयात शुल्क कम किए गए। सॉफ्टवेयर निर्यात को लाइसेंस मुक्त उद्योग घोषित किया गया।

1990 के दशक में तथा 2000 के बाद व्यापक नीति सुधारों का क्रम जारी रहा। आयात प्रशुल्कों को कम करते-करते लगभग शून्य कर दिया गया। तथा व्यापक पैमाने पर दूरसंचार विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति दी गई; सुविधाएँ उपलब्ध कराई गयीं। इसके अलावा इस अवधि में होने वाले प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप Data storage, Transmission cost में तेज गिरावट हुई। Internet Service providers को देश में ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार तथा पनडुब्बी शीर्ष केबल स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई। उन्हें किराए पर विदेशी उपग्रहों से Bandwidth लेने की अनुमति भी दी गई। इससे Internet bandwidth की अधिक व व्यापक स्तर पर उपलब्धि संभव हो सकी तथा देश में Internet का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। National Long Distance तथा ISD दूरसंचार सेवाओं को भी खोल दिया गया। देश में इन्टरनेट Internet के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार, तथा देश के महत्वपूर्ण सेक्टरों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने Information Technology Act 2000 लागू किया। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक कामर्स तथा इलेक्ट्रॉनिक समझौतों को मान्यता प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिए electronic filing/ documention को संभव बनाने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षर इत्यादि के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।

Scanned with CamScanner

उदारीकरण शुरू होने के बाद से सेवाओं के निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 में 4.6 बिलियन डॉलर के सेवाओं के निर्यात 2015-16 में 154.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। भारत के सॉफ्टवेयर एवं IT निर्यातों + व्यापारिक सेवा निर्यातों में तेजी आई, तेज वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

परन्तु कुछ आलोचकों का मत है कि सेवा क्षेत्र पर अधिक जोर देना और यह मान लेना कि वह ~~प्रक्रिया~~ भविष्य में भी सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर बनाए रखने में सफल होगा गलत है। 2002 में अपने लेख में शंकर आचार्य ने मत व्यक्त किया था कि "सेवाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं परन्तु वे केवल अपने बलबूते पर भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च व धारणीय संवृद्धि दर बनाए नहीं रख सकतीं"; इस संदर्भ में शंकर आचार्य ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं।

(1) हमारा ऐतिहासिक रिकार्ड इस बात को सिद्ध नहीं करता कि सेवा क्षेत्र अग्रगामी क्षेत्र है। 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी जो औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि से अधिक रही। परन्तु इस दशक में भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष संवृद्धि हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सेवा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में काफी ज्यादा संवृद्धि हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक संवृद्धि दर सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर से अधिक थी। ग्यारहवीं योजना की अवधि में वर्ष 2011-12 को छोड़कर 2012-13 तथा 2013-14 में पाया जाता है कि सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में, अधिक रही। वर्ष 2015-16 में सेवा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली संवृद्धि दर में कोई खास अन्तर नहीं था।

(2) सेवा क्षेत्र में कई नितान्त भिन्न स्वरूप के उपक्षेत्रों को मिलाया जाता है। इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्पादन का अनुमान लगाना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसलिए उत्पादन के आंकड़े उतने विश्वसनीय नहीं माने जा सकते जितने वस्तु उत्पादक क्षेत्रों के होते हैं। इस आधार पर सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित उत्पादन तथा संवृद्धि के सरकारी आंकड़ों पर सन्देह व्यक्त किए जा सकते हैं।

(3) शंकर आचार्य ने सबसे तेज ~~गति~~ गति से विकास करने वाले सात विकासशील देशों ~~के~~ के दीर्घकालिक विकास रिकार्ड का अध्ययन किया है। ये देश हैं: कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, चीन, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड, मलेशिया तथा इंडोनेशिया। इस अध्ययन से यह पता लगा कि इन सात देशों में से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें सेवा क्षेत्र की संवृद्धि औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि से अधिक रही हो। सिंगापुर में इन दोनों क्षेत्रों की संवृद्धि दरें समान थीं, बाकी छः देश में उद्योग क्षेत्र की संवृद्धि, सेवा क्षेत्र की संवृद्धि से अधिक थी।

(4) जहाँ तक नौवीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र की उच्च संवृद्धि ~~दर का~~ ~~प्रश्न है~~ मात्र 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। जब सेवा क्षेत्र में संवृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के उच्च स्तर पर थी तब भी वह सकल घरेलू उत्पाद के बाकी के आधे हिस्से की 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम संवृद्धि दर की भरपाई नहीं कर पाई। इसलिए केवल सेवा क्षेत्र ही सकल घरेलू उत्पाद की उच्च धारणीय संवृद्धि सुनिश्चित नहीं कर सकता।

पानागड़िया के अनुसार "यदि भारत को दो दशक से कम अवधि में आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है तो औद्योगिकरण के चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि नहीं है कि आधुनिक सेवा क्षेत्र transition strategy का केन्द्र-बिन्दु नहीं बनाया जा सकता। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में जो शक्ति व मजबूती दिखाई दी है तथा तेज औद्योगीकरण के संदर्भ में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की उपेक्षा करना मूर्खता होगी। भारत को आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर अपने विकास-पथ पर दोनों टांगों पर चलना होगा। परंपरागत उद्योगों, खासतौर पर अकुशल श्रम-प्रधान विनिर्माण, तथा आधुनिक सेवा सेक्टर जैसे सॉफ्टवेयर तथा संचार, इनमें से प्रत्येक 'टांग' को उपयुक्त विशिष्ट नीतियाँ अपनाकर और मजबूत बनाना होगा।" पानागड़िया ने इस युक्ति को "दो टांगों पर चलने की नीति (walking on two legs)" कहा है।